इमलीपुरा में अवैध कारखाने पर चला नगर निगम का बुलडोजर

निगम के दो लापरवाह अधिकारी निलंबित

नवभारत न्यूज़

खंडवा। नगर निगम ने शहर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए इमलीपुरा स्थित अनवर कुरैशी द्वारा संचालित अवैध कारखाने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है।

नगर निगम की इस कार्रवाई को शहर में अवैध निर्माण और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ बड़ी चेतावनी माना जा रहा है।महापौर अमृता अमर यादव ने प्रेस वार्ता में बताया कि संबंधित संचालक को स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगर निगम की ओर से तीन बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।

इसके बाद नियमानुसार अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई संभवत: कल तक जारी रहेगी। महापौर ने स्पष्ट किया कि नगर निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या अवैध निर्माण की सूचना मिलने पर भविष्य में भी इसी तरह कठोर कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था और नियमानुसार विकास सुनिश्चित करना निगम की प्राथमिकता है।

> इस मामले में लापरवाही बरतने वाले दो अधिकारियों अमित अग्रवाल (प्रभारी सहायक राजस्व निरीक्षक), जाकिर अहमद (पशुवध गृह प्रभारी अधिकारी) पर निलंबन की कार्रवाई की। साथ ही निगम प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन प्रतिष्ठानों के ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ है, उनके खिलाफ तत्काल सीलिंग की कार्रवाई की जाए। महापौर ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन और मुख्यमंत्री की मंशा अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने की है। नगर निगम उसी दिशा में कार्य करते हुए शहर को सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

200 क्विंटल गेहूं जब्त कर दो गोदाम किए सील

शिवपुरी. जिले में अवैध अनाज भंडारण और अनियमितताओं पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर बदरवास कस्बे में छापेमारी कर गोदाम सील किया गया और भारी मात्रा में अनाज जब्त किया गया।कोलारस एसडीएम अनूप श्रीवास्तव, बदरवास तहसीलदार सचिन भार्गव और अनाज मंडी कर्मचारियों की टीम को अवैध खरीद और भंडारण की सूचना मिली थी। इसके बाद घुरवार रोड स्थित नंदनी ट्रेडर्स पर कार्रवाई की गई।जांच में सामने आया कि संचालक राजेंद्र किरार बिना वैध लाइसेंस के अनाज की खरीद और भंडारण कर रहा था, जो नियमों का उल्लंघन है। दुकान के पास स्थित गोदाम की तलाशी में लगभग 200 क्विंटल गेहूं सहित बड़ी मात्रा में अन्य अनाज बरामद हुआ, जिसे प्रशासन ने जब्त कर लिया.

सीएम यादव ने जाना किसानों का हाल

01 लाख रुपए से अधिक का कृषक को भुगतान

06 तौल कांटों पर निरंतर तुलाई कार्य चलता रहे

भोपाल, 30 अप्रैल .मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरूवार को खरगोन जिले में मंडलेश्वर तहसील के कतरगांव और शाजापुर जिले के ग्राम मकोड़ी में गेहूँ उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने उपार्जन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कलेक्टर और मंडी सचिव को निर्देशित किया कि गेहूँ उपार्जन से संबंधित सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें.अन्नदाताओं को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वे निरंतर आकस्मिक दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे.

> मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कतरगांव में कृषक श्री सुरेश पाटीदार की 55 क्विंटल गेहूँ की खरीदी के बाद ई-उपार्जन पोर्टल पर श्री पाटीदार को प्राप्ति ऑनलाइन जनरेट करवाई और कृषक को भुगतान राशि 1 लाख 44 हजार 374 रूपये का प्राप्ति पत्र सौंपा .मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को महेश्वर में रात्रि विश्राम के बाद आज खरगोन जिले में कतरगांव गेहूँ उपार्जन केंद्र के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर और मंडी सचिव को निर्देशित किया कि उपार्जन/खरीदी केंद्रों पर पूरे 6 तौल कांटे लगाए जाएं .सभी 6 तौल कांटों पर निरंतर तुलाई कार्य चलता रहे . गेहूं खरीदी के आज से नए मापदंड जारी हुए है वह लागू हो जाएं .

फाइनेंस कंपनी के 8 मैनेजरों ने किया 25 लाख का गबन

जबलपुर. अधारताल थाना अंतर्गत संचालित भारत फाइनेंशियल इनक्लूजन लिमिटेड शाखा के ही 8 फील्ड अधिकारियों (संगम मैनेजर) ने बैंक के साथ विश्वासघात करते हुए महिलाओं से वसूली गई किस्तों के लगभग 25.24 लाख रुपये का गबन कर निजी उपयोग में खर्च कर दिए और बैंक में जमा नहीं किए, जब ब्रांच मैनेजर ने उनसे पैसे लौटाने को कहा, तो आरोपियों ने धमकाते हुए साफ कह दिया कि जो करना है कर लो, पैसे नहीं मिलेंगे. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर ली है .

कार्य में लापरवाही : 33 प्राचार्यों का वेतन रोका

दो दर्जन प्राचार्य व सभी बीआरसीसी पर होगी कार्रवाई

ग्वालियर, 30 अप्रैल. कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी ने नामांकन कार्य में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है. जारी आदेश के तहत दो दर्जन प्राचार्य एवं समस्त बीआरसीसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. वहीं 33 प्राचार्यों का वेतन रोका गया है.

आयुक्त लोक शिक्षण एवं संभागीय बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्वालियर जिला नामांकन कार्य में राज्य ग्रेडिंग में 40वें नंबर पर है। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों ने अप्रसन्नता व्यक्त की है। रिपोर्ट के अनुसार 28 अप्रैल तक जिले का नामांकन केवल 84 प्रतिशत है, जिसे असंतोषजनक बताया गया है. आदेश में कहा गया कि पत्रों, वेबीनार, व्हाट्सएप और दूरभाष से लगातार निर्देश देने के बावजूद प्रगति नहीं हुई. जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों पर ध्यान न देते हुए नामांकन कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का परिचय दिया गया है तथा अपने पदीय दायित्व का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं किया है. नामांकन कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है. नियत समय पर प्रगति न होने या जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही की जाएगी. मुरार ग्रामीण, मुरार शहरी क्रमांक 1 व 2, डबरा, घाटीगांव, भितरवार के समस्त बीआरसीसी को यह पत्र भेजा गया है. नामांकन में 40वें स्थान पर आने से नाराज जिला शिक्षा अधिकारी ने बीआरसीसी को नोटिस जारी किया है.

184 नोटिस मिलने के बाद अब कांग्रेस की इंट्री

कांग्रेस ने दी अतिक्रमण हटाने पर आंदोलन की चेतावनी

टीकमगढ़, 30 अप्रैल. सेल सागर तालाब पर प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर सियासत गरमा गई है. गुरुवार को कांग्रेस ने इस कार्रवाई का खुलकर विरोध किया और प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि गरीबों के साथ अन्याय हुआ तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा.

कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष गौरव शर्मा ने आरोप लगाया कि नगर पालिका ने भाजपा कार्यालय को बचाने के लिए लोगों को नोटिस जारी किए हैं. उन्होंने बताया कि जिस जमीन पर भाजपा कार्यालय बना हैए वह सेल सागर तालाब की जमीन है. जमीन मालिक ने भाजपा कार्यालय के निर्माण के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है.शर्मा के अनुसार नगर पालिका ने यह नोटिस जमीन मालिक पर दबाव बनाने के लिए जारी किए हैंए ताकि वे भाजपा कार्यालय के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले लें. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर हाल में गरीब और जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ी है.कांग्रेस नेता ने प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बिना उचित पुनर्वास के लोगों को हटाने की तैयारी की जा रही है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है. गौरव शर्मा ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों को बेघर करना स्वीकार नहीं किया जाएगा.उन्होंने मांग की कि पहले प्रभावितों को वैकल्पिक व्यवस्था दी जाएए उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो. शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्दबाजी में कदम उठाया और मकान तोड़े तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी.इस मुद्दे को लेकर शहर में भी हलचल बढ़ गई है और प्रभावित परिवारों में चिंता का माहौल है. कांग्रेस ने इसे जनहित का मुद्दा बताते हुए बड़ा आंदोलन खड़ा करने के संकेत दिए हैं. आज कांग्रेसी नेताओं ने सेल सागर तालाब पहुंचकर प्रभावित लोगों से मुलाकात की.

50 क्विं . से ज्यादा डोडाचूरा की बड़ी खेप पकड़ी

नशीले पदार्थों के खिलाफ नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई

नीमच। नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई के तहत सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (सीबीएन) नीमच ने 50 क्विंटल से अधिक डोडाचूरा की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि उपयोग में लिया गया कंटेनर ट्रक भी जब्त कर लिया गया।

सीबीएन मध्यप्रदेश इकाई को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 29 अप्रैल को आगरा-भरतपुर हाईवे पर सेवर (भरतपुर) स्थित कदमकुंज रिसोर्ट के पास एक संदिग्ध टाटा कंटेनर ट्रक को रोका गया। तलाशी लेने पर ट्रक में छिपाकर रखी गई 252 बोरियों से कुल 5096.11 किलोग्राम डोडाचूरा बरामद हुआ।

जांच में सामने आया कि हरियाणा नंबर का यह ट्रक झारखंड क्षेत्र से मारवाड़ की ओर अवैध मादक पदार्थ लेकर जा रहा था। सूचना मिलते ही सीबीएन नीमच की टीम ने निगरानी बढ़ाते हुए संदिग्ध वाहन को चिन्हित कर इंटरसेप्ट किया और चालक को हिरासत में लिया।पूछताछ में आरोपी ने ट्रक में डोडाचूरा छिपाकर ले जाने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए मादक पदार्थ और वाहन को जब्त कर आरोपी को एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से जनता त्रस्त, अधूरे कार्यों ने बढ़ाया आक्रोश

बीड़। क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है।

बीड-मुंदी मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों ने जहां यातायात को प्रभावित किया है, वहीं विभागीय लापरवाही पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, ग्राम मोहद रोड पर जिस कार्य को 27 दिनों में पूरा किया जाना था, वह समय पर पूरा नहीं हो सका। इस दौरान एक युवक की दर्दनाक मौत भी हो गई, लेकिन इसके बावजूद विभाग की कार्यशैली में सुधार नहीं आया। वर्तमान में भी बीड-मुंदी रोड दिन में कई बार बंद और चालू किया जा रहा है, जिससे बस संचालकों और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर, पर हाल ही में कराए गए निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे हैं।

> जानकारी के अनुसार, सुलगांव के एक ठेकेदार द्वारा लगभग 14 फीट नाली का निर्माण किया गया था, लेकिन इसमें मानकों की अनदेखी करते हुए बेहद कम सामग्री का उपयोग किया गया। आरोप है कि मात्र कुछ बोरी सीमेंट और सीमित सामग्री में काम पूरा कर दिया गया, जिसके चलते 15 दिनों के भीतर ही मार्ग पुन: क्षतिग्रस्त हो गया और रास्ता बंद करना पड़ा।इस पूरे मामले में विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एसडीओ सीमा सागर द्वारा कार्य को मंजूरी दे दी गई, जबकि गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया।लगातार हो रही इन घटनाओं से क्षेत्रीय जनता में रोष व्याप्त है। लोगों ने मांग की है कि निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए .

10 लाख के सामुदायिक भवन के बिलों में धांधली

मामला खंडवा जिले की ग्राम पंचायत मालूद का

नवभारत न्यूज

किल्लौद। जनपद पंचायत किल्लौद की ग्राम पंचायत मालूद में अजा/अजजा विभाग के अंतर्गत सामुदायिक भवन निर्माण में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी गई हैं। 2018 में स्वीकृत 10 लाख रुपए की राशि का बंदरबांट करने के लिए सरपंच, सचिव और उपयंत्री ने मिलकर फर्जी बिलों और बेहिसाब भुगतानों का ऐसा मकड़जाल बुना है कि विभाग के होश उड़ गए हैं।

चौंकाने वाली बात यह है कि जिस कार्य की स्वीकृति 19 अप्रैल 2018 को मिली थी, उसे पूर्ण होने में 8 साल लग गए और फरवरी 2026 में काम खत्म होने के बावजूद आज तक इसका कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सका है। यह देरी खुद-ब-खुद भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही है, क्योंकि रिकॉर्ड में लगभग पूरी राशि 9,97,440 रुपए ठिकाने लगाई जा चुकी है।इस पूरे निर्माण कार्य में भुगतानों का गणित इतना उलझा हुआ और संदिग्ध है कि

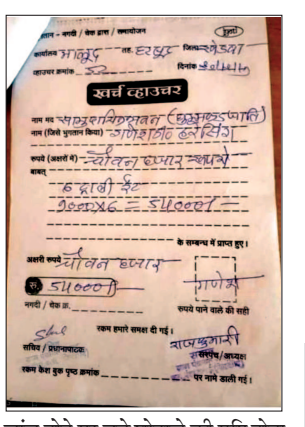

जांच होने पर बड़े घोटाले की पुष्टि होना तय है। महेश नामक व्यक्ति के खाते में पुताई और ईंटों के नाम पर हजारों रुपए डाले गए, लेकिन कहीं भुगतान का विवरण गायब है तो कहीं बिल और वाउचर का अता-पता नहीं है। हद तो तब हो गई जब 54,000 रुपए की राशि महेश के खाते में भेजी गई, लेकिन वाउचर गणेश पिता हरे सिंह के नाम का लगाया गया, जो सीधे तौर पर कागजों में हेराफेरी और फर्जीवाड़े का प्रमाण है। इसके अलावा 27,000 रुपए के एक अन्य भुगतान का तो बिल तक रिकॉर्ड में नहीं दर्शाया गया है, जिससे साफ है कि सरकारी पैसे को निजी जेबों में भरने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया गया। भ्रष्टाचार का यह खेल केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खिड़कियां के अरमान खान और अमन ट्रेडर्स को भी लाखों रुपए के भुगतान नियम विरुद्ध तरीके से किए गए। 1.72 लाख, 1.11 लाख और 1.37 लाख जैसी भारी-भरकम राशियों के भुगतान में चंद बिलों का सहारा लेकर पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया गया है।

> अनारसिंह, रामविलास, मानक, जेश, संजू मीणा और इस्माइल खान जैसे कई नामों का उपयोग कर फर्जी बिलों की झड़ी लगा दी गई ताकि सरकारी बजट को ठिकाने लगाया जा सके। सरपंच, सचिव और उपयंत्री की इस जुगलबंदी ने अनुसूचित जनजाति बस्ती के विकास के नाम पर मिले फंड को आपसी बंदरबांट की भेंट चढ़ा दिया है। अब क्षेत्र की जनता और जागरूक ग्रामीण इस पूरे निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं ताकि कागजों पर चल रहे इस विकास के पीछे छिपे असली चेहरों को बेनकाब किया जा सके।

कफ सिरप कांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट में छिंदवाड़ा के बहुचर्चित सिरप कांड की सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराये जाने को लेकर याचिका दायर की गई है. जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए मामले में लिप्त आरोपी डॉ प्रवीण सोनी, ज्योति सोनी व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जबलपुर निवासी अधिवक्ता अश्मिता चंद ने याचिका दायर कर पुलिस एवं प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर लापरवाही और मामले को कमजोर करने के आरोप लगाए गए हैं. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता केके पांडेय एवं सिद्धार्थ एस पांडेय ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कफ सिरप के सेवन से लगभग 26 मासूम बच्चों की दर्दनाक मृत्यु हो गईए जबकि कई अन्य बच्चों को गंभीर स्वास्थ्य हानि एवं स्थायी अंग क्षति का सामना करना पड़ा. इतनी बड़ी घटना के बावजूद पुलिस ने केवल सामान्य एवं जमानती धाराओं में अपराध दर्ज कर मामले की गंभीरता को कम करने का प्रयास किया है.

याचिका में यह भी कहा गया है कि संबंधित दवा के निर्माण वितरण और बिक्री में शामिल व्यक्तियों एवं अधिकारियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक प्रावधान लागू नहीं किये गये है.

जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 को मिल रही गति

आलीराजपुर। आलीराजपुर जिले के जनपद पंचायत भाबरा अंतर्गत ग्राम पंचायत रिंगोल में जल संरक्षण की दिशा को गति दी जा रही है। कलेक्टर नीतू माथुर के मार्गदर्शन में 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के तहत 'डगवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर' का निर्माण कर कुओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम रिंगोल के लाड़ी वारिया फलिया निवासी रणछोड़ भारता के खेत पर डगवेल रिचार्ज संरचना का निर्माण मनरेगा योजना के माध्यम से किया गया है। इससे वर्षा जल के बेहतर संचयन में सहायता मिलेगी, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि के साथ-साथ आसपास के जल स्त्रोतों में भी सुधार देखने को मिलेगा।

गुंडा टैक्स न देने पर ननि सुपरवाइजर पर हमला

जबलपुर. रांझी थाना अंतर्गत बापू नगर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने पहुंचे नगर निगम के सुपरवाइजर पर दबंगों ने न केवल शासकीय कार्य में बाधा डाली, बल्कि गंदगी फैलाई. सुपरवाइजर ने मना किया तो उन्होंने गुंडा टैक्स की मांग करते हुए बेसबॉल के डंडे से हमला कर घायल कर दिया.

पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस के अनुसार रांझी निवासी

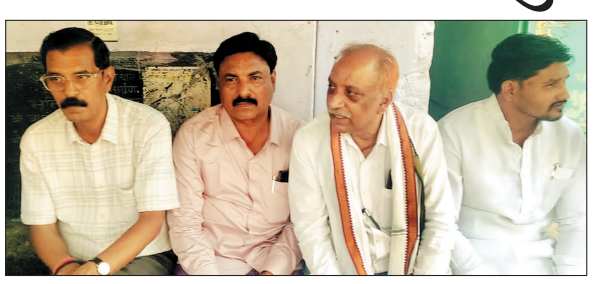

फरीद खान नगर निगम में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ हैं. बुधवार दोपहर करीब 12 बजे जब वे बापू नगर क्षेत्र में सफाई कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे, तो वहां बाबू सोनकर और सूरज सोनकर गंदगी फैला रहे थे. फरीद खान ने जब उन्हें ऐसा करने से मना किया, तो आरोपियों ने सुपरवाइजर पर अवैध वसूली का दबाव बनाया. आरोपियों ने फरीद खान को धमकाते हुए कहा कि तुम बहुत कमीशन कमा रहे हो, हमें भी इसमें हिस्सा चाहिए. जब सुपरवाइजर ने इसका विरोध किया, तो बाबू और सूरज ने अपने साथियों लक्ष्मण सोनकर, पप्पू सोनकर और ऋषभ सोनकर को बुला लिया. विरोध करने पर पांचों आरोपियों ने मिलकर फरीद खान के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोपियों ने गुंडा टैक्स न देने पर जान से मारने की धमकी दी और बेसबॉल के डंडे से हमला कर फरीद खान को घायल कर दिया. घटना के बाद घायल सुपरवाइजर, जोन प्रभारी नरेश शर्मा, अनिल मिश्रा (अतिरिक्त कमिश्नर, नगर निगम) और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ थाने पहुंचे. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर पांचों आरोपियों बाबू, सूरज, लक्ष्मण, पप्पू और ऋषभ सोनकर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.

निर्देश | उपमुख्यमंत्री ने रीवा शहर में जल प्रदाय योजना और सीवरेज कार्यों की समीक्षा की

सभी निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें : डिप्टी सीएम

भोपाल, 30 अप्रैल. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में रीवा शहर में संचालित जल प्रदाय योजना एवं सीवरेज सिस्टम से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता, समय-सीमा तथा वित्तीय प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए. उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं, ताकि आम नागरिकों को समय पर सुविधाओं का लाभ मिल सके.

बैठक में अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय दुबे, आयुक्त संकेत भोंडवे सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे. उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने जल प्रदाय व्यवस्था के शेष सभी कार्य, विशेषकर ओवरहेड वाटर टैंक के निर्माण एवं जल वितरण नेटवर्क का विस्तार, आगामी वर्षा ऋतु से पहले हर स्थिति में पूर्ण करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये. उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों के दौरान नागरिकों की दैनिक जीवनचर्या प्रभावित न हो, इसके लिए कार्यों को सुनियोजित एवं चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाए. आमजन की सुविधा एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर उन्होंने बल दिया.

> सीवरेज सिस्टम की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने शेष पाइपलाइन बिछाने के कार्य तथा हाउस सर्विस कनेक्शनों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सीवरेज नेटवर्क का समय पर पूर्ण होना शहरी स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, अत: इसमें किसी प्रकार की देरी न हो. उन्होंने एसटीपी निर्माण कार्य को भी प्राथमिकता से पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए.

मिड टाउन में 2 वर्ष की मासूम की डूबने से मौत

घर में नहीं मिली तो तलाश के दौरान टंकी में मिली

नवभारत न्यूज

रतलाम। शहर के मिड टाउन कॉलोनी में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 2 साल की मासूम बच्ची की पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया और खुशियों का माहौल मातम में बदल गया।

मृतका काव्या, पिता रोहन सबरवाल, सुबह करीब 11:30 बजे घर में खेल रही थी। इसी दौरान वह अचानक परिजनों की नजरों से ओझल हो गई। काफी देर तक बच्ची दिखाई नहीं देने पर परिवार के लोगों ने घर के हर कोने में तलाश शुरू की। दो मंजिला मकान होने के

कारण ऊपर-नीचे सभी जगह खोजबीन की गई, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चला।

आखिरकार बच्ची के चाचा जुगल ने घर के पोर्च में बनी पानी की टंकी में देखा, जहां काव्या बेसुध हालत में पड़ी मिली। यह दृश्य देखते ही परिवार के होश उड़ गए।

परिजन तत्काल उसे लेकर रोटरी गार्डन के सामने स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन बच्ची को सरकारी मदर चाइल्ड केयर यूनिट (एमसीएच) लेकर पहुंचे, जहां डॉ. प्रतीक आर्या ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।